# *फिनटेक के अवसर और चुनौतियां**

*शक्तिकांत दास*

मुझे बड़ी खुशी है कि नीति आयोग की फिनटेक संगोष्ठी (कॉनक्लेव) 2019 में शामिल हूँ और उस तकनीकी क्रांति पर अपने विचार साझा कर रहा हूँ जो वित्त के भविष्य को आकार दे रही है। विशेष रूप से मैं आभारी हूँ नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कंठ का जिन्होंने मुझे इस गरिमामय सभा में आमंत्रित किया । जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस संगोष्ठी का केंद्र भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र है और वे कदम भी जो फिनटेक से जुड़ी वृद्धि, रोजगार, व समावेश की संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं । फिनटेक के व्यापक कैनवास को देखते हुए, मैं इस क्षेत्र के कुछ मूलभूत विषयों पर अपने विचार रखूँगा।

सामान्यत: फिनटेक का अर्थ वित्तीय तकनीक (फाइनैंशियल टेक्नॉलॉजी) है और यह उन वित्तीय नवोन्मेषों के बारे में बताता है जो तकनीक पर आधारित हैं। 'नये छोटे उद्यमों' ('स्टार्ट-अप्स') से लेकर बड़ी टेक-कंपनियों (बिग-टेक्स) और स्थापित वित्तीय संस्थानों तक सभी प्रमुख खिलाड़ी, वित्तीय सेवाओं के वैल्यू चेन में इस तकनीकी प्रगति के प्रयोग से अंतिम उपयोक्ता को चुस्ती, कुशलता और भिन्नता का अनुभव दे रहे हैं। इस आंदोलन में वित्तीय परिदृश्य में बुनियादी बदलाव लाने की संभावना है जहाँ उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विकल्पों के वृहत्तर वर्ग से चुनाव कर सकेंगे और ऑपरेशनल लागत में कमी से वित्तीय संस्थाओं के लिए कार्यक्षमता को बेहतर करने का अवसर है। एक देश के रूप में जो वहनीय लागत पर सभी के लिए वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारे लिए यह निर्णायक समय है और हमें इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए।

**भारत में फिनटेक अनुभव**

भारत इस क्रांति की अग्रणी पंक्ति में रहा है। फिनटेक अपनाने पर हाल के एक वैश्विक सर्वे के अनुसार 52 प्रतिशत की दर के साथ भारत का स्थान इसमें दूसरा है। रिपोर्ट है कि भारत में 1218 फिनटेक फ़र्में हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया है। वे निवेश की एक स्वस्थ प्रवृत्ति भी तैयार कर रही हैं।

विगत वर्षों में रिज़र्व बैंक ने "कम-नकदी" समाज के लक्ष्य की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया है। ध्येय रहा है एक ऐसी भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम) देना जिसमें पहले से तेज प्रोसेसिंग की तकनीकों का प्रयोग हो और जो एक साथ संरक्षा, सुरक्षा, अधिक सुविधा व पहुँच की खूबियों से लैस हो। वहनीय लागत, अंतर-परिचालनीयता तथा ग्राहक जागरुकता व संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बैंक भुगतान सेवाओं के पारंपरिक माध्यम रहे हैं। तथापि, तकनीकी परिवर्तन की तेज गति के साथ, इस क्षेत्र में बैंकों का एकाधिकार नहीं रहा। बैंक से इतर इकाइयां, इसमें हाथ भी बँटा रही हैं और बैंकों से पंजा भी लड़ा रही हैं, या तो बैंको को तकनीकी सेवा देकर या सीधे खुदरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस देकर। भुगतान के मैदान में बैंकेतर इकाइयों की इस अधिक भागीदारी को विनियामक ढाँचे ने भी प्रोत्साहित किया है।

हाल के वर्षों में, चाहे इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आइएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भारत बिल पे सिस्टम (बीबीपीएस) हो या आधार-आधारित भुगतान सेवा (एईपीएस) हो एक अत्याधुनिक भुगतान आधार संरचना और तकनीक का प्लेटफॉर्म विकसित करने की पुरजोर कोशिश की गई है। इससे देश का खुदरा (रिटेल) भुगतान परिदृश्य बदल गया है। पिछले पाँच वर्षों में रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की कुल मात्रा नौ-गुना बढ़ गई है।

अब मैं डिजिटल पेमेंट से संबंधित कुछ आँकड़े बताता हूँ। एनईएफटी सिस्टम ने 2017-18 में मात्रा में 4.9 गुणा वृद्धि करते हुए 195 करोड़ की संख्या में लेन-देन किए और मूल्य में 5.9 गुणा वृद्धि करते हुए लगभग 172 लाख़ करोड़ रुपए के। इसी प्रकार 2017-18 में क्रेडिट और डेबिट कार्डों के लेन-देन की

* नीति आयोग की फिनटेक संगोष्ठी में सोमवार 25 मार्च 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में दिया गया भाषण।

[1] ईवाई फिनटेक एडोप्शन सूचकांक 2017, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf पर उपलब्ध है।

संख्या क्रमश: 141 करोड़ और 334 करोड़ रही। प्रीपेड पेमेंट इनस्ट्रूमेंट (पीपीआई) ने लगभग 346 करोड़ लेन-देन का रिकॉर्ड बनाया जिसका मूल्य 1.4 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार मात्रा की दृष्टि से वर्ष 2017-18 में कुल कार्ड भुगतान कुल ख़ुदरा भुगतान (रिटेल पेमेंट्स) के 52 प्रतिशत पर रहा।

बैंकिंग टेक्नलॉजी और ट्रेड फ़ाइनैंस के क्षेत्रों में हुआ विकास भी प्रशंसनीय रहा है। उधार देने व पूँजी उगाहने के वैकल्पिक स्वरूप सामने आ रहे हैं तथा इनमें पारंपरिक उधारदाताओं के बाजार समीकरण और पारंपरिक मध्यस्थों की भूमिका को बदल डालने की संभावना है। क्राउड फंडिंग, जिसमें निवेशकों के एक बड़े समूह से बाह्य वित्त उगाहा जाता है, भारत में बड़ी शैशवास्था में है। समकक्षी या पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेंडिंग, जिसके लिए आरबीआई ने अक्टूबर 2017 में मास्टर निदेश जारी किए, में लघु और मझोले उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता को बेहतर करने की सामर्थ्य है। ग्यारह इकाइयों को पी2पी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने का लाइसेंस दिया गया है। सात विशुद्ध डिजिटल लोन कंपनियों (एनबीएफसी) को भी रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस दिया है और कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी है। यद्यपि, वे खिलाड़ी विशुद्ध रूप से डिजिटल हैं और मोबाइल एप्लीकेशन्स के माध्यम से ही कार्य कर रहे हैं, हमने यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम एक भौतिक उपस्थिति तो उनकी अवश्य रहे ताकि जरूरत पड़ने पर ग्राहक उन तक पहुँच पाए।

इसके अतिरिक्त, सात भुगतान बैंक काम शुरू कर चुके हैं। तकनीक-चालित ये बैंक, ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने और अपने काम-काज, दोनों में फिन-टेक का प्रयोग करते हैं।

इनवॉयस ट्रेडिंग भारत में फिनटेक एप्लीकेशन का दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो शैशवावस्था में है। यह एमएसएमई की सहायता करता है जिन्हें पेमेंट में देर के कारण प्राय: कार्यकारी पूँजी (वर्किंग कैपिटल) और नकदी के प्रवाह (कैश फ्लो) की समस्या रहती है। रिज़र्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) स्थापित किया है जो फाइनैंसिंग की एक नवोन्मेषी व्यवस्था है जहाँ बिलों व इनवॉयस की डिस्काउंटिंग के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए तीन इकाइयां प्राधिकृत की गई हैं और धीरे-धीरे मात्रा बढ़ रही है।

दूसरा प्रयास अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) के लिए एक विनियामक ढाँचे की स्थापना है। कुल पाँच इकाइयों को एनबीएफसी-एए के रूप में सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है और 2019-20 में उनके कार्य प्रारंभ कर देने की प्रत्याशा है।

फिनटेक के जरिये डिजिटल पेमेंट की पैठ एवं वित्तीय समावेश के विस्तार को और बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्री नंदन निलेकनी की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यी समिति नियुक्त की है।

फिनटेक की क्रांति जहाँ अवसरों का एक नया विश्व खोलती है, वहीं विनियामकों व पर्यवेक्षकों के लिए जोख़िम और चुनौतियां भी पेश करती है। इस विकास-क्रम की संभावनाओं के पूर्ण दोहन के लिए आवश्यक है कि इन जोखिमों को जल्द चिह्नित किया जाए और उनसे संबंधित वियामक व पर्यवेक्षी चुनौतियों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। अत: मैं विशेषत: भारतीय संदर्भ में इन अवसरों, जोख़िमों व चुनौतियों पर एक विहंगम दृष्टि डालना चाहूँगा और नीतिगत मार्ग पर भी जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

**अवसर, जोखिम और भावी मार्ग**

सर्वप्रथम मैं डिजिटल ऑनबोर्डिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अवसरों पर परकश डालूँगा।

*डिजिटल ऑनबोर्डिंग और वित्तीय समावेशन*

दो ऐसे क्षेत्र जहां भारतीय संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए: पहला, फिनटेक प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय प्लैटफ़ार्म तक पहुँच से संबंधित है; और दूसरा ऐसे संभावित जोखिमों के विश्लेषण के बारे मेन है जो फिनटेक अपनाने के कर्ण हो सकते हैं। वित्तीय रूप से वंचित जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित वित्तीय उत्पादों को तैयार करना, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और निवेश की मात्र को प्रोत्साहित करना प्रथम उद्देश्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण है। आधार इकोसिस्टम का प्रभावी उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

के मामले में हो रहा है। इस संबंध में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कदम है- इस प्लेटफार्म पर अब तक लगभग एक सौ मिलियन केवाईसी रिकॉर्ड को अपलोड किया जा चुका है। हमें प्रभावी तरीके से अंतर-क्षेत्रीय और असमानताओं को दूर करने के लिए और विवादों का ऑनलाइन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बहुभाषी वित्तीय साक्षरता और एक मजबूत शिकायत निवारण मशीनरी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

*रेगटेक और सुपटेक*

जहां तक संभावित जोखिम और उसके उसको कम करने की बात है, **रेगटेक**[2] और **सुपटेक**[3] की महत्वपूर्ण भूमिका है। विनियामकों और पर्यवेक्षकों को ऑफसाइट सतर्कता को बढ़ाना होगा। इसके लिए एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी युक्त और डेटा प्रधान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नए क्षेत्रों जैसे रेगटेक और सुपटेक की शुरुआत हो गई है। दोनों प्रौद्योगिकी का उद्देश्य ऑटोमेशन के प्रयोग के माध्यम से कार्य-दक्षता में सुधार लाना, नई क्षमताओं को शुरू करना और कार्य को आसान बनाना है। रिज़र्व बैंक मेन हम डाटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए सुपटेक का प्रयोग कर रहे हैं। के लिए कुछ नाम हैं- इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मानिट्रिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस), एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मानिट्रिंग सिस्टम (ईडीपीएमएस) और सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी)। बैंकों का जोखिम आधारित पर्यवेक्षण भी व्यापक रूप से डाटा प्रधान है और यह सुपटेक का एक उदाहरण है। रेगटेक और सुपटेक का भविष्य बिग डाटा अनालिटिक्स, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, मचीनी ज्ञान, क्लाउड कम्प्यूटिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग, देता ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बायोमेट्रिक्स आदि पर टिका हुआ है।

एक सुदृढ़ जोखिम संस्कृति, जिसमें जोखिमों का पता लगाना, उसका मूल्यांकन करना और उसमें कमी बैंक के स्टाफ सदस्यों के दैनिक कार्य का अंग है, उभरते जोखिमों के प्रबंधन की सफलता का केंद्र बिन्दु होगी। इसी प्रकार, अव्यवहारिक रिन वृद्धि, पहले की तुलना में अधिक अंतरसमबद्धता, प्रतिचक्रियता, पर्यवेक्षी ढांचे से बाहर नई गतिविधियों के विकास और निम्न लाभ के कारण हुए वित्तीय जोखिमों ने प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा दिया है। फिनटेक उत्पादों के लिए जोखिम दूसरे देशों के कानूनी और विनियामी मामलों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। डाटा की गोपनीयता और ग्राहक सुरक्षा ऐसे बड़े क्षेत्र हैं, जिस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रोत्साहित किया है कि फिनटेक फर्मों के साथ नए-नए संपर्क स्थापित करने की संभावना तलाशें क्योंकि नवोन्मेष के माध्यम से वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में ऐसा करने से काफी मदद मिलेगी। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में निवेश का प्रवाह निर्बाध बना रहे ताकि इसका संपूर्ण रूप से दोहन किया जा सके। इसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना आवश्यक है जो आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करे। साथ ही, इस निहितार्थ पर भी सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा जो समष्टि अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

फिनटेक के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रणाली में उनके प्रभाव को सुप्रवाहित करने के लिए तथा ग्राहकों के संरक्षण और सभी हितधारियों के हितों की सुरक्षा के लिए हमें समुचित विनियमी और पर्यवेक्षी ढांचे की जरूरत होगी। ऐसे ढांचे को इस क्षेत्र की संवृद्धि अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध जोखिमों को दूर करना चाहिए। फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर बने रिजर्व बैंक के कार्यसमूह (फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर बने रिजर्व बैंक के कार्यसमूह की रिपोर्ट, 2017) ने फिन टेक समाधानों के साथ अनुभव करने के लिए, सुपरिभाषित स्पेस और अवधि के अंतर्गत एक विनियामी सैंडबॉक्स/इनोवेशन हब की शुरुआत करने का सुझाव दिया है, जहां पर असफलता के परिणामों को रोका जा सके और असफलता के कारणों का विश्लेषण किया जा सके। एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कम दाम पर नवोन्मेषी उत्पाद शुरू करके समय घटाकर फिनटेक कंपनियों की मदद करेगा। भविष्य में

[2] रेगटेक एक ऐसा एप्लिकेशन या प्लैटफ़ार्म है जो विनियमी अनुपालन को स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से और अधिक प्रभावी बना देता है तथा अनुपालन की लागत को कम करता है। रेगटेक ऐसी प्रोद्योगिकी पर फोकस करता है जो विनियमी अपेक्षाओं की प्रदानगी को और अधिक दक्ष और प्रभावी बनती है।

[3] सुपटेक एक ऐसी प्रोद्योगिकी है जो विनियमकों और पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण का समर्थन करने के लिए प्रयोग की जाती है। सुपटेक का उद्देश्य अबाध और सीधा डाटा संग्रहण/रिपोर्टिंग, डाटा विश्लेषण और निर्णय लेना, सुप्रवाही लाइसेंसिंग, बाजार निगरानी और सतर्कता, केवाईसी/एएमएल/सीएफ़टी, साइबर सुरक्षा या साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है।

रिज़र्व बैंक एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्थापित करेगा। इसके लिए अगले 2 महीनों में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

**निष्कर्ष**

निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूँगा कि फिनटेक में संभावना है कि यह भारत में वित्तीय सेवाओं और वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को मौलिक रूप से नई शक्ल प्रदान कर सकता है। इससे लागत में कमी आ सकती है और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। हमें प्रणालीगत प्रभावों को कम करते हुए, फिनटेक का प्रभावशाली तरीके से उपयोग करके एक संतुलन स्थापित करना है। प्रोद्योगिकी को सम्र्थ्यशाली बनाकर और जोखिमों का प्रबंधन करके, हम एक ऐसी वित्तीय प्रणाली तैयार कर सकते हैं जो अधिक समवेशी, लागत-प्रभावी और लचीली हो।

धन्यवाद।